प्रेरणा

कोशिश कर हल निकलेगा
आज नहीं तो कल निकलेगा..!

सच कहने की ताकत

साप्ताहिक समाचार पत्र

जालंधर ब्रीज

जल है तो कल है

www.jalandharbreeze.com • JALANDHAR BREEZE • WEEKLY • YEAR-6 • 09 AUGUST TO 15 AUGUST 2024 • VOLUME 03 • PAGE-4 • RATE-3.00/- • RNI NO.: PUNHIN/2019/77863

Lic No : 933/ALC-4/LA/FN:1184

INNOVATIVE TECHNO INSTITUTE

CONSULTING DESIGN TRAINING

ISO CERTIFIED 2015 COMPANY

✓ STUDY ✓ WORK ✓ SETTLE IN ABROAD

Low Filing Charges &
*Pay Money after the Visa

•IELTS •STUDY ABROAD

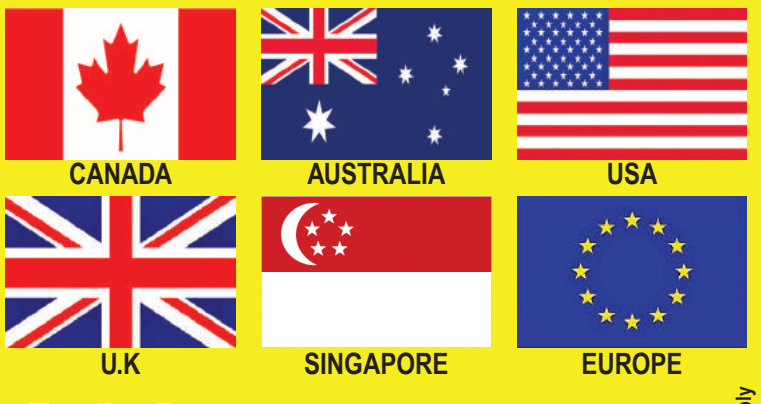

E-mail : hr@innovativetechin.com • Website : www.innovativetechin.com • FB/Innovativetechin • Contact : 9988115054 • 9317776663

REGIONAL OFFICE : S.C.O No. 10 Gopal Nagar, Near Batra Palace, Jal. HEAD OFFICE : S.C.O No. 21-22, Kuldip Lal Complex, Highway Plaza GT Road, Adjoining Lovely Professional University. Phagwara.

*T&C apply

पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल

नई दिल्ली. भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया। काफी उतार-चढ़ाव वाले इस मैच में भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने दो गोल दागे और भारत ने बढ़त को बनाए रखा। पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी लेकिन दूसरे क्वार्टर के बाद से खेल और रोमांचक होता गया। भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई नेताओं ने बधाई दी।

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि एक उपलब्धि जिसे आने वाली पीढियां याद रखेंगी। भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में चमकी, कांस्य पदक जीता। ये और भी खास है क्योंकि ये ओलंपिक में उनका लगातार दूसरा पदक है। उनकी सफलता कौशल, दृढ़ता और टीम भावना की जीत है। उन्होंने अत्यधिक धैर्य दिखाया। खिलाड़ियों को बधाई। हर भारतीयों का हॉकी से भावनात्मक जुड़ाव है और ये उपलब्धि इस खेल को हमारे देश के युवाओं के बीच और भी लोकप्रिय बनाएगी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हमारी हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। यह पांच दशक से भी अधिक समय के बाद हुआ है जब भारत ने लगातार दो ओलंपिक खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारतीय हॉकी के पुनरुत्थान के लिए टीम सबसे अधिक प्रशंसा की पात्र है। उन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इस टीम द्वारा दिखाई गई निरंतरता, कौशल, एकजुटता और जुझारूपन हमारे युवाओं को प्रेरित करेगा। भारतीय हॉकी टीम, बहुत बढ़िया।

गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा कि पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर हमारी पुरुष हॉकी टीम को बहुत-बहुत बधाई। आपका दमदार प्रदर्शन और कौशल खेल के लिए एक नया उत्साह जगाएगा। आपकी उपलब्धि ने तिरंगा का गौरव बढ़ाया है।

पीआर श्रीजेश की यादगार जीत के साथ विदाई

8 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मैच में भारतीय टीम के यादगार प्रदर्शन में गोलकीपर पीआर श्रीजेश का अहम रोल रहा। अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे अनुभवी गोलकीपर पी आर श्रीजेश पूरे टूर्नामेंट में चट्टान की तरह भारतीय गोल की रक्षा करते रहे और शानदार विदाई ली। पदक का रंग बदलने का सपना टूटने के बावजूद उन्होंने कहा था कि अब उनके पास आखिरी मौका है और पदक अभी भी जीता जा सकता है।

गोलपोस्ट पर डट कर खड़े रहे श्रीजेश ने अपना वादा पूरा किया।

पंजाबी खिलाड़ियों को एक-एक करोड़ के इनाम की घोषणा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। मान ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन पूरे देश का नाम रोशन किया है। हॉकी टीम में कप्तान हरमनप्रीत सिंह और वाइस-कप्तान सहित 10 खिलाड़ी पंजाब के हैं, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में शानदार हॉकी खेली। हरमनप्रीत सिंह ने 10 गोल किए। इन खिलाड़ियों को राज्य सरकार की नीति के अनुसार एक-एक करोड़ रुपए के नकद इनाम से नवाजा जाएगा।

मान ने कहा कि 52 साल बाद पहली बार भारत ने ओलंपिक्स में हॉकी में लगातार दो बार पदक जीता है। भारत ने टोक्यो और पेरिस में हुई ओलंपिक खेलों में अब लगातार दो पदक जीते हैं। इससे पहले लगातार दो पदक 1968 में मैक्सिको और 1972 में म्यूनिख में जीते गए थे।

ड्रग इंस्पेक्टर से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी, 6.69 करोड़ रुपए की राशि वाले 24 बैंक खाते फ्रीज

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) ने ड्रग इंस्पेक्टर शिशान मित्तल के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 24 बैंक खातों को, जिनमें कुल 6.69 करोड़ रुपए जमा थे, को सील कर दिया और बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी मुद्रा भी जब्त की है। डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने आज यहां बताया कि यह छापेमारी ड्रग इंस्पेक्टर शिशान मित्तल पर लगे आरोपों के तहत चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई। उस पर अवैध दवाओं और मेडिकल स्टोर्स से संबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी में मदद करने और अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी खातों में ड्रग मनी जमा करने का आरोप लगाया गया था। यह छापेमारी बठिंडा, मौर मंडी, गिद्दड़बाहा, मोहाली, चंडीगढ़ और हरियाणा के फतेहाबाद समेत आठ विभिन्न स्थानों पर की गई।

डीजीपी ने बताया कि पुलिस द्वारा फ्रीज किए गए बैंक खाते आरोपी ड्रग इंस्पेक्टर के नाम पर थे और उसके रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी खाते भी थे, जिनमें कुल 6.69 करोड़ रुपए जमा थे। उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा तीन बैंक लॉकर भी जब्त किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने लगभग 9.31 लाख रुपए नकद, 260 ग्राम सोना और 515 दिरहाम बरामद किए हैं। इसके अलावा अवैध गतिविधियों से हासिल की गई कई संपत्तियों का भी पता चला है, जिसमें ज़ीरकपुर में 2 करोड़ रुपए के फ्लैट, डबवाली में 40 लाख रुपए के प्लॉट समेत कई अन्य संपत्तियां शामिल हैं।

सहकारी सभा में तैनात इंस्पेक्टर रिश्वत लेते पकड़ा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने भूरा कोहना बहुउद्देशीय सहकारी सभा में तैनात सहकारिता इंस्पेक्टर गुरिंदर सिंह से 1,90,000 रुपये की बेहिसाबी राशि बरामद की है। इस कर्मचारी को बीते दिन 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। राज्य विजीलेंस ब्यूरो के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उक्त आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया और अदालत ने आगे की पूछताछ के लिए उसे दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी की तलाशी के दौरान विजीलेंस ब्यूरो की टीम द्वारा 1,90,000 रुपये बरामद किए गए, लेकिन वह इस राशि के स्रोत को जायज नहीं ठहरा सका। उसके खिलाफ विजीलेंस ब्यूरो के थाना अमृतसर में भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर 'पंजाब सहायता केंद्र' समर्पित किया

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

दुनिया भर में बसे पंजाबी भाईचारे को बड़ी सुविधा प्रदान करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज यहां के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 पर 'पंजाब सहायता केंद्र' के नाम से उच्च स्तर का एनआरआई सुविधा केंद्र लोगों को समर्पित किया। इस सहायता केंद्र की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पंजाब इस प्रकार की पहल करने वाला देश का पहला राज्य है, जिससे राज्य सरकार की एनआरआई समुदाय की सहायता और सहयोग करने की दृढ़ प्रतिबद्धता प्रकट होती है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र 24 घंटे कार्यशील रहेगा और इस टर्मिनल पर आने वाले एनआरआई और अन्य यात्रियों को सहायता प्रदान करेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस केंद्र के पास दो इनोवा गाड़ियाँ होंगी, जो यात्रियों को पंजाब भवन या अन्य निकटवर्ती स्थानों पर पहुंचाने में सहायता करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यात्री या उनके रिश्तेदार किसी भी समय उड़ानों के आने, उड़ानों के समय, टैक्सी सेवा, हवाई अड्डे पर खो गए सामान की जानकारी के लिए या अन्य सहायता के लिए इस केंद्र तक पहुँच सकते है। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रकार की आपात स्थिति आती है तो नई दिल्ली स्थित पंजाब भवन, कापरनिकस मार्ग में कुछ कमरे भी यात्रियों और उनके रिश्तेदारों को दिए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि किसी भी सहायता के लिए 011-61232182 पर संपर्क किया जा सकता है।

महिला पहलवान विनेश फोगाट की घटना के बारे में सहायक स्टाफ की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना ने पूरे खेल जगत को आहत किया है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने लाखों खेल प्रेमियों के दिलों को गहरी ठेस पहुंचाई है, जिस कारण इसकी निष्पक्ष जांच करवाना समय की मांग है।

मोहाली एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने की मांग

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

श्री आनंदपुर साहिब से सांसद मालविंदर सिंह कंग ने लोकसभा में एक विधेयक पर अपनी मांग रखते हुए कहा कि शहीद-ए-आज़म भगत सिंह के नाम पर बने शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मोहाली से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि पंजाब के लोगों को फ़ायदा मिल सके। सांसद मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि एक मीडिया ग्रुप के सर्वे के मुताबिक़ पंजाब से 25 फ़ीसदी यात्री प्रतिदिन 10 हज़ार रुपये खर्च कर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विभिन्न देशों में जाने के लिए अपनी फ्लाइट्स पकड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार मोहाली के भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में बढ़ौतरी कर देती है, तो चंडीगढ़ से दिल्ली तक सड़क यातायात पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा, जिससे लोग ट्रैफिक और प्रदूषण से बच सकेंगे।

वक्फ बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश

नई दिल्ली. विपक्ष की भारी आपत्ति के बीच केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया। बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की अनुशंसा की गई। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि मैं सभी दलों के नेताओं से बात करके इस संयुक्त संसदीय समिति का गठन करुंगा। रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक का उद्देश्य किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं है और संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है। लोकसभा में विधेयक पेश किए जाने पर कई विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाया, इसलिए संशोधन की योजना बनाई गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों जनता दल (यूनाइटेड) और तेलुगू देसम पार्टी (तेदेपा) ने विधेयक का समर्थन किया, हालांकि, तेदेपा ने इसे संसदीय समिति के पास भेजने की पैरवी की।

न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग

विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में दी जानकारी

• **जालंधर ब्रीज.** नई दिल्ली

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348(1)(ए) में यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। हालाँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (2) में यह प्रावधान है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस राज्य में अपनी मुख्य पीठ वाले उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी भाषा, या राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली किसी अन्य भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। इसके अलावा, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में यह कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी या राज्य की आधिकारिक भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर सकता है। अगर कोई निर्णय, डिक्री या आदेश किसी ऐसी भाषा (अंग्रेजी भाषा के अलावा) में पारित या दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय के अधिकार के तहत उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी संलग्न होगा। राजभाषा नीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए नियुक्त मंत्रिमंडल समिति ने 21.05.1965 को आयोजित

अपनी बैठक में यह निर्धारित किया था कि उच्च न्यायालय में अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा के प्रयोग से संबंधित किसी भी प्रस्ताव पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना के बारे में रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 36/2016 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 13.07.2016 के निर्णय के माध्यम से उपर्युक्त मुद्दे को आधिकारिक निर्णय के लिए संवैधानिक पीठ को भेजने का निर्णय उचित समझा। मामला वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

न्यायिक कार्यवाही और फैसलों को आम नागरिक की समझ के लिए अधिक व्यापक बनाने के लिए, कार्यवाही और निर्णयों का अंग्रेजी से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचित किया गया है, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एआई टूल का उपयोग करके ई-एससीआर निर्णयों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता में एआई सहायता प्राप्त कानूनी अनुवाद सलाहकार समिति का गठन किया है। दिनांक 02.12.2023 तक, एआई अनुवाद टूल का उपयोग करके, सर्वोच्च न्यायालय के 31,184 निर्णयों का 16 भाषाओं- हिंदी (21,908), पंजाबी (3,574), कन्नड़ (1,898), तमिल (1,172), गुजराती (1,110), मराठी (765), तेलुगु (334), मलयालम (239), ओडिया (104), बंगाली (39), नेपाली (27), उर्दू (06), असमिया (05), गारो (01), खासी (01), कोंकणी (01) में अनुवाद किया गया है। दिनांक 02.12.2023 तक 16 भाषाओं में अनुवादित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का विवरण सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के ई-एससीआर पोर्टल पर उपलब्ध है।

सभी उच्च न्यायालयों में संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अध्यक्षता में एक इसी तरह की समिति गठित की गई है। अब तक, सर्वोच्च न्यायालय ई-एससीआर निर्णयों का 16 स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने में उच्च न्यायालयों के साथ सहयोग कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 4,983 निर्णयों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया है और उच्च न्यायालयों द्वारा इसे अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अपलोड किया गया है।

विधि एवं न्याय मंत्रालय के तत्वावधान में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में 'भारतीय भाषा समिति' का गठन किया है। यह समिति कानूनी सामग्री का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के उद्देश्य से सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान शब्दावली विकसित कर रही है।

अब तक कुछ क्षेत्रीय भाषाओं जैसे-गुजराती, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में एक सीमित शब्दावली भी विकसित की गई है। ये शब्दावलियाँ कानूनी प्रणाली के सभी हितधारकों के उपयोग के लिए विधायी विभाग की वेबसाइट http://legislative.gov.in/glossary-in-regional-language/ पर उपलब्ध हैं।

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

फर्जी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र बेचने से संबंधित मामले में 22 निजी व्यक्तियों को दो वर्ष की कारावास

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/जयपुर

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), श्रीगंगानगर (राजस्थान) की अदालत ने फर्जी अंकतालिकाओं एवं प्रमाण पत्रों की बिक्री से संबंधित एक मामले में कश्मीर सिंह, सुरेंद्र सिंह, मलकीत सिंह, गुरपाल सिंह, परमजीत सिंह, खुशविंदर सिंह, चंदर सिंह, कृष्ण कुमार बिश्नोई, बलदेव सिंह पुत्र मोहर सिंह, गुरजिंदरपाल सिंह, पंकज चोपड़ा, हरगुरनाथ सिंह, मुकेश कुमार गर्ग, मंदीप सिंह, राजपाल सिंह, मनजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, बलवीर सिंह, केवल सिंह, बलदेव सिंह पुत्र जीत सिंह एवं जसमत सिंह सहित 22 निजी व्यक्तियों को दो वर्ष की कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।

सीबीआई ने दिनांक 30.09.1997 को इस मामले को अपने हाथों में लिया। एक शिकायत के आधार पर पूर्व में यह मामला श्रीगंगानगर जिले के सदर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या 301/1996 के तहत दर्ज किया था। सीबीआई ने 25 आरोपियों के विरुद्ध 21 अप्रैल, 1999 को आरोप पत्र दायर किया तथा आरोपियों के विरुद्ध औपचारिक रूप से 2003 को आरोप तय किए गए। सुनवाई पूरी होने के पश्चात, अदालत ने 22 आरोपियों को दोषी ठहराया एवं उन्हें तदनुसार सजा सुनाई। दो आरोपियों के विरुद्ध उनकी मृत्यु के कारण विचारण रोक दिया गया जबकि एक आरोपी को नाबालिग होने के कारण अदालत ने बरी कर दिया।

दुबई की इन जगहों पर जाना बिल्कुल न करें मिस

• **जालंधर ब्रीज.** फीचर

दुबई एक बेहद आलीशान और खूबसूरत शहर है। ये उन जगहों में शामिल है जहां जाने का सपना लगभग हर घुमक्कड़ का होता है। यहां की ऊंची इमारतें, नाइटलाइफ, शानदार शॉपिंग मॉल और तरह-तरह के लजीज जायके इस जगह को खास बनाते हैं। इस जगह ज्यादातर लोग परिवार के साथ जाना पसंद करते हैं। इस जगह पर बीच से लेकर डेजर्ट तक का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नेचर लवर हों या फिर एडवेंचर के शौकीन हर किसी के लिए ये जगह अच्छी मानी जाती है। ये शहर दुनियाभर में अपनी अलग पहचान बना चुका है। अगर आप भी यहां जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जानिए यहां घूमने की जगह और दुबई जाने का बेस्ट टाइम-

TRAVELLING

दुबई घूमने के लिए एक बेस्ट प्लेस है। परिवार के साथ यहां जाना पसंद किया जाता है। इस जगह पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो जानिए यहां घूमने की बेस्ट प्लेस और जाने का सही समय।

दुबई में घूमने की जगह

बुर्ज खलीफा

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा देखने लायक है। यहां पर आप दुनिया के सबसे ऊंचे रेस्तरां पर जाएं। ये 122वीं मंजिल पर है। यहां बैठकर खाने का मजा अलग ही एक्सपीरियंस होगा। कहते हैं कि दुबई में बुर्ज खलीफा देखे बिना ट्रिप अधूरा होगा।

पाम जुमेराह

पाम जुमेराह का प्रतिष्ठित मानव निर्मित द्वीप अपने ट्रेडमार्क ताड़ के पेड़ के आकार के लिए फेमस है। यहां पर समुद्र तट पर बंगले, आलीशान बुटीक, लक्जरी होटल और महंगे रेस्तरां हैं।

दुबई डेजर्ट सफारी

हॉलीवुड-बॉलीवुड फिल्मों में दुबई के इस डेजर्ट सफारी को देखा होगा। यहां की डेजर्ट सफारी लोगों को बहुत लुभाती है। यहां रेत के टीलों पर जीप या जिप्सी, ऊंट की सवारी, क्वैड बाइक, सैंड बोर्डिंग आदि चलाई जाती हैं।

दुबई फाउंटेन

दुबई फाउंटेन 24 एकड़ में बुर्ज झील के बीच में बना हुआ है। साथ ही ये शानदार बुर्ज खलीफा के सामने है। बड़े-बड़े फव्वारों से निकलते पानी और उसमें दिखती रंग बिरंगी लाइट्स देखकर मजा आ जाएगा।

दुबई म्यूजियम

दुबई म्यूजियम शहर का सबसे पुराना संग्रहालय है। इस म्यूजियम से अमीरात के इतिहास के बारे में देख सकते हैं। यहां आपको दुबई से जुडी कहानियों का शानदार परिचय देखने को मिल जाएगा।

क्या है दुबई जाने का बेस्ट टाइम?

दुबई एक अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन है। जहां घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च है। यह पीक सीजन है, इस दौरान थोड़ी भीड़ की उम्मीद होती है। पीक सीजन में दुबई का मौसम साफ नीला आसमान और हल्की ठंडी शामें होती हैं।

BOLLYWOOD

कपड़ों पर खर्च कर पछताती हैं तो, जानें कैसे कम होगा शॉपिंग एडिक्शन

अलमारी खोलते ही कपड़े गिरने के लिए तैयार हैं, पर जब कहीं जाने की बारी आती है, तो आप 'क्या पहनूं' जैसे सवाल लेकर बैठ जाती हैं। कपड़ों के बेहतर मैनेजमेंट की मदद से कैसे इस समस्या से पाएं छुटकारा, बता रही हैं शाश्वती।

• **जालंधर ब्रीज .** फीचर

दुनिया भर में लोगों की औसत आमदनी में इजाफा हुआ है, तो खर्च करने की ताकत भी बढ़ी है। इस ताकत को हवा देने का काम कर रही है, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग ने न सिर्फ खरीदारी को आसान बना दिया है बल्कि बढ़ावा भी दिया है। कपड़ा और फुटवियर ब्रांड पब्लिक डिजायर द्वारा कपड़ों के बाजार, उनकी कीमत और खरीदारी संबंधी आदतों के बारे में एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में पाया गया कि एक औसत भारतीय साल में लगभग दो लाख रुपये सिर्फ कपड़ों की खरीदारी पर खर्च करता है। इन खरीदारों में महिलाएं सबसे आगे हैं।

कपड़ों की इतनी ज्यादा खरीदारी करने और कपड़ों से भरी अलमारी होने के बावजूद किसी महिला के मुंह से यह सुनना कि 'मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। क्या पहनूं?' बहुत आम बात है। पर, जब आप अपनी आमदनी का एक अच्छा-खासा हिस्सा कपड़ों की खरीदारी पर ही खर्च कर रही हैं तो फिर किसी खास मौके पर पहनने के लिए आपके पास कपड़े क्यों नहीं होते? सच्चाई तो यह है कि आपके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं है। समस्या सही खरदारी और उनके रख-रखाव से जुड़ी है। और यह एक ऐसी समस्या है, जिससे थोड़ी कोशिश से आप छुटकारा पा सकती हैं। क्या करें कि कपड़ों की कमी का रोना आपको कभी ना रोना पड़े, आइए जानें:

सोच-समझकर करें खरीदारी

मॉल खरीदारी करने गईं। अपने पसंदीदा ब्रांड पर डिस्कॉउंट का बोर्ड देख और ढेर सारे कुर्ते खरीद लाईं। पर, क्या उन कुर्तों को खरीदते वक्त आपने यह सोचा कि उनकी मैचिंग का लोअर आपके पास है या नहीं? शर्ट, टी-शर्ट, स्कर्ट या फिर कुर्ता...आपको जो भी पसंद आए, उसका बिल चुकाने से पहले यह जरूर सोचें कि क्या आपके पास उसके साथ पहनने के लिए मैचिंग कपड़ा पहले से है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो या तो उस कपड़े को पहनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी या फिर उसके साथ पहनने के लिए लोअर की खरीदारी आपको अलग से करनी पड़ेगी। सोच-समझकर खरीददारी करेंगी तो शौक से खरीदे गए कपड़े को पहन भी पाएंगी।

ट्रेंड के पीछे क्यों भागना

बेल बॉटम का ट्रेंड आया तो वो खरीद लिया। क्रॉप टॉप का ट्रेंड शुरू हुआ तो तरह-तरह के रंग में उसे खरीद लिया। किसी खास स्टाइल की ड्रेस लोकप्रिय हुई, तो उसे ही खरीद डाला। अधिकांश लोग जो यह शिकायत करते हैं कि उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, असल में ड्रेंड के पीछे भागकर खरीदारी करने वाले लोग होते हैं। ट्रेंड को अपनाने में कुछ गलत नहीं है। पर, अपनी अलमारी को ट्रेंडी कपड़ों से भर देने से बात नहीं बनने वाली। सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बेसिक कपड़ों में निवेश करें। फुटवियर से लेकर सफेद टी-शर्ट तक। जब बेसिक कपड़े और एक्सेसरीज आपके पास होंगे, तो ट्रेंडी कपड़ों की स्टाइलिंग भी आपके लिए आसान हो जाएगी और कपड़ों की कमी आपको कभी नहीं खलेगी।

बंद कीजिए एक जैसे कपड़े खरीदना

कपड़ों से जुड़ी हम सब की आदतें थोड़ी अजीब-सी होती हैं। कोई पैटर्न पसंद आया तो उसी पैटर्न में अलग-अलग रंगों के ढेर सारे कपड़े खरीद लिए। फिर चाहे वह चेक पैटर्न वाला शर्ट हो या फिर कोल्ड शोल्डर वाली टॉप। पर, एक ही पैटर्न के ढेर सारे कपड़ों से अलमारी भर लेने से क्या फायदा? ऐसा करने से आपके कपड़ों की कमी नहीं दूर होने वाली। एक जैसे पैटर्न वाले कपड़ों को अलमारी में एक जगह रखें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके पास एक तरह के कितने कपड़े हैं और भविष्य में वैसा ही कुछ खरीदने से पहले आप सचेत हो जाएंगी।

अच्छा नहीं ज्यादा विकल्प होना

जैसे कम विकल्प होने से यह सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या पहनूं, ठीक वही समस्या बहुत ज्यादा विकल्प होने से भी होती है। जब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, तो उसके सामने खड़े होकर कपड़ों के ढेर को घूरने के अलावा और चारा ही नजर नहीं आता। जिस तेजी से आप कपड़े खरीदती हैं, उतनी ही तेजी से उन कपड़ों को अलमारी से हटाएं भी जिन्हें आपने लंबे समय से नहीं पहना है। या फिर उन कपड़ों को भी अलमारी से बाहर का रास्ता दिखाएं, जो आपके मौजूदा स्टाइल से मेल नहीं खाती। जब अलमारी में संतुलित संख्या में कपड़े होंगे तो आपको उनके साथ ज्यादा रचनात्मक होने का और नए-नए प्रयोग करने का मौका मिलेगा।

ताकतवर मेवा है बादाम, खाने के फायदे

अपने बच्चे की याददाश्त बेहतर बनाने के लिए उसे तो आप हर दिन बादाम देती हैं, फिर खुद क्यों नहीं खातीं? बादाम सेहत के लिए किस तरह से है फायदेमंद और कैसे इसे बनाएं नियमित आहार का हिस्सा...

• **जालंधर ब्रीज.** रेसिपी

मखाने की चर्चा होते ही मन में यह खयाल आता है कि यह तो सर्दियों में खाया जाने वाला ड्राई फ्रूट है। पर, ऐसा है नहीं। कुछ मेवे ठंडी तासीर वाले होते हैं, जिनमें से एक मखाना भी है। मखाना, जिसे अंग्रेजी में फॉक्स नट या लोटस सीड के नाम से भी जाना जाता है। इसके सेवन से पेट को ठंडक मिलती है साथ ही वीगन और शाकाहारी लोगों के लिए पोषक तत्वों से भरपूरा मखाना एक अच्छा विकल्प है।

कैसा होता है मखाना?

मखाना गोल, छोटा और मोती जैसे सफेद होते हैं। इन्हें तीन भागों में वर्गीकृत करती हूं: पहले टाइप का मखाना साबुत, गोल और आकार में थोड़ा बड़ा होते हैं। दूसरे टाइप के मखाने आकार में थोड़े छोटे होते हैं, जिनमें काले छिलके ज्यादा दिखाई देते हैं। तीसरे प्रकार के मकान को टुर्री मखाना कहते हैं क्योंकि यह बहुत छोटे व सस्ते होते हैं, पर कुछ लोग इनका इस्तेमाल खीर बनाने के लिए करते हैं। आइए जानें मैं इनका उपयोग अपनी प्रतिदिन की डाइट में कैसे करती हूं:

- मैं मखाना का प्रयोग अपने भोजन में तीन तरह से करती हूं-पहला कच्चे रूप में, दूसरा भुने और तीसरा पाउडर बनाकर।
- मखाने से काला छिलका हटाकर मखाने को दो टुकड़ों में करती हूं और फिर पानी में भिगोकर धोकर पंचामृत में डालती हूं ।
- कच्चे मखानों को साफ करके दो टुकड़े करके एक चम्मच घी में जीरा, राई का तड़का लगाकर ऐसे ही डाल देती हूं। फिर सेंकती हूं। ऊपर से प्याज, टमाटर और खीरा का कचूंबर बनाकर इस मखाने में मिलाती हूं। स्वादिष्ट नाश्ता तैयार है।
- एक चम्मच घी में 10-12 मिनट धीमी गैस पर क्रिस्पी होने तक मखाने को भूनती हूं। फिर नमक, काली मिर्च, चाट मसाला आदि डालकर ठंडा करके एअर टाइट डिब्बे में रख लेती हूं। चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खाने के लिए यह सेहतमंद विकल्प है।
- मखाने को भून लें। फिर बिना पानी डाले गुड की चाशनी बनाकर उसमें मखाना डालें। मखाने को गुड़ की चाशनी में मिलाएं। ठंडा होकर हर मखाना अलग हो जाता है। बच्चों को यह बहुत पसंद आता है।
- भुने मखानों का बादाम के साथ पाउडर बनाकर एयर टाइट डिब्बे में रखती हूं। डिनर में सूप के साथ पनीर, मखाने की टिक्की बनाती हूं या रात में दूध में एक चम्मच मखाना पाउडर डालकर पीती हूं।
- भुने मखाने को खीर में डालें या सब्जी में,स्वाद अच्छा हो जाता है। इसके अलावा भुने मखानों को बारिश के मौसम में पकौड़े वाले बेसन के मिश्रण में डुबोकर डीप फ्राई करें। खाने में मजा आ जाएगा।
- सलाद के ऊपर मखानों को क्रश करके डालें या साबुत ही तुरंत सर्व करें, अच्छा रहेगा। साथ ही स्मूदीज में, शेक में मखाने के पाउडर का इस्तेमाल करती हूं।
- रायते में भुने मखाने और पिस्ता डालें। ऊपर से हींग, जीरा पाउडर, नमक और मिर्च आदि डालें। चाहें तो सिर्फ भुने मखानों को चाट की तरह बनाएं या भेलपुरी की तरह। खाने का मजा दोगुना हो जाएगा।
- मैं काजू रोल की तरह मखाना रोल और लड्डू आदि बनाती हूं। इसके अलावा छिलके सहित भुने चने को पीसकर बराबर मात्रा में मखाना पाउडर, ड्राई फ्रूट

और देसी खांड मिलाकर लड्डू बनाती हूं।

यूं करें स्टोर

- पैकेट खोलते ही मखानों को एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डालें। इससे हवा और नमी कंटेनर में प्रवेश नहीं करेगी ।
- ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें। धूप गर्मी और नमी से दूर रखें ताकि उनका कुरकुरापन बना रहे।
- मखानों को रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए। मखाना खराब हो सकता है।

फायदा मिलेगा भरपूर

- खाने में सोडियम, पोटैशियम, कैल्शियम, फाइबर, आयरन और विटामिन-सी जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और कमजोरी दूर होती है। 100 ग्राम मखाने में 350 ग्राम कैलोरी पाई जाती है। यह वजन कम करने और दिल को सेहतमंद रखने में प्रभावी साबित होता है।

पहली बार कॉलेज जाने वाला है आपका बच्चा,पैरेंट्स के नाते जरूर सिखा दें ये 4 बातें

जालंधर ब्रीज (फीचर) . भीड़ से अलग होकर सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने बच्चों को देखना, सभी पैरेंट्स के दिल की ख्वाहिश होती है। लेकिन इसके लिए कदम-कदम पर उन्हें रास्ता दिखाना भी पेरेंट्स का ही काम होता है। खासतौर पर जब बच्चे अपनी स्कूल लाइफ को कंप्लीट करके कॉलेज की दुनिया में कदम रखने जाते हैं, उस टाइम पर पेरेंट्स की गाइडेंस की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है।

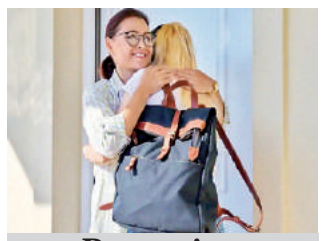

बच्चों को उनकी जिम्मेदारियां समझाएं : स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में बहुत अंतर होता है। जहां स्कूल में बच्चों को हमेशा डिसिप्लिन में रहना होता है वहीं कॉलेज पहुंचते ही उन्हें थोड़ी आजादी मिल जाती है। ऐसे में पेरेंट्स को अपने बच्चों को कॉलेज लाइफ में मिलने वाली आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को भी समझाना चाहिए। बच्चों को समझाना चाहिए कि कॉलेज में उन्हें आजादी इसलिए मिलती है कि बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो खुलकर विचार कर सकें और अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले ले सकें। आजादी मिलने का मतलब मनमानी करना बिल्कुल नहीं है।

जरूर सिखाएं सेल्फ सिक्योरिटी : स्कूल से निकल कर जब बच्चा कॉलेज पहुंचता है तो कई चीजें एकदम से चेंज हो जाती है। स्कूल में जाने वाले बच्चों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्कूल की होती है ऐसे में पेरेंट्स बिल्कुल फ्री रहते हैं। लेकिन जब बच्चा कॉलेज पहुंचता है तो पेरेंट्स को उनकी सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा चिंता होती है। बच्चों को समझाएं कि कॉलेज में कुछ भी गलत होने पर सबसे पहले वो आपको इसकी जानकारी दें। कॉलेज में बने नए दोस्तों की हर बात पर आंख बंद कर भरोसा ना करें।

बच्चों के दोस्त बनें पैरेंट्स : स्कूल खत्म कर के जब बच्चा कॉलेज पहुंचता है तब इस एज में माता-पिता को एक दोस्त की तरह बच्चे के साथ खड़ा रहना चाहिए। बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर करने के बजाय प्यार से उनके दिल की बातों को समझना चाहिए। बच्चों को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो खुलकर आपसे हर बात शेयर कर सकें। ऐसा करने से आपको अपने बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रहेगी। जिससे आप उसे सही गलत के बारे में समझा पाएंगे।

समझाएं मनी मैनेजमेंट : बच्चा जब स्कूल छोड़कर कॉलेज में पहुंचता है तो उसे पैसे की वैल्यू समझाना बहुत जरूरी है। खासतौर पर जब बच्चा घर छोड़कर किसी दूसरे शहर या हॉस्टल में शिफ्ट होता है तो ऐसे में उसे पैसे का मैनेजमेंट कैसे किया जाए यह समझाना जरूरी है। क्योंकि ये पहली बार है, जब बच्चा अपनी जिम्मेदारियां खुद से उठा रहा है।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

बीपी कंट्रोल करके दिल की सेहत का रखती है ख्याल 'लोटस टी'

HEALTH

आयुर्वेद के अनुसार कमल के फूल की चाय को बेस्ट औषधि माना गया है। कमल के फूलों से बनी चाय पीने से व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द और जलन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है।

• **जालंधर ब्रीज.** हेल्थ केयर

सुबह की शुरूआत से लेकर दिन भर की थकान मिटाने के लिए अगर एक प्याली चाय की जरूरत पड़ती है तो यह खबर आप जैसे टी लवर्स के लिए है। जी हां, बदलते वक्त के साथ भले ही दूध की चाय ने ग्रीन टी, ब्लेक टी जैसी चाय की जगह ले ली हो। लेकिन आज भी कुछ लोग अपनी फेवरेट चाय के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इसी तरह के एक हेल्दी एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा है कमल के फूल की चाय। आयुर्वेद के अनुसार कमल के फूलों में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणो के साथ कई तरह के मिनरल्स जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और क्लोरीन पाए जाते हैं। इतना ही नहीं कमल के फूल कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का हेल्दी स्रोत होते हैं। कमल के फूलों को आयुर्वेद में बेस्ट औषधि माना गया है। कमल के फूलों से बनी चाय पीने से व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द और जलन जैसी समस्याओं में राहत मिल सकती है। आइए जानते हैं आयुर्वेदिक एक्सपर्ट दीक्षा भावसार से क्या है कमल के फूलों से बनी चाय पीने के फायदे और इसे बनाने का सही तरीका। बता दें, दीक्षा ने कमल के फूल की चाय पीने से फायदों को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया है।

कमल के फूलों से बनी चाय पीने के फायदे

दिल की सेहत : कमल के फूल में विटामिन बी, सी, आयरन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। डॉ दीक्षा भावसार के अनुसार कमल की चाय कार्डियक अरेस्ट जैसी दिल से जुड़ी समस्याओं में टॉनिक की तरह काम करती है।

ब्लड प्रेशर रखें कंट्रोल : कमल के फूल से बनी चाय ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी फायदेमंद हो सकती है। नियमित रूप से इस चाय को पीने से हाई बीपी की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन आप अगर लो बीपी से परेशान रहते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही इसका सेवन करें।

स्ट्रेस से राहत : कमल के फूल में एपोमोर्फिन और न्यूसीफेरिन नामक मौजूद पोषक तत्व स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजायटी से जील करने में मदद कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार नियमित तौर पर कमल के फूल से बनी चाय पीने पर दिमाग शांत रखने में मदद मिल सकती है।

प्यास रखें कंट्रोल : जिन लोगों को जरूरत से ज्यादा प्यास लगती है उनके लिए भी कमल की चाय बेहद फायदेमंद है। कमल की चाय में मौजूद पोषक तत्व प्यास शांत करने में मदद कर सकते हैं। कमल के फूल की चाय शरीर का तापमान ठंडा बनाए रखने में भी मदद करती है।

पीरियड्स के दर्द में आराम : पीरियड्स के दौरान जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द और ऐंठन की समस्या बनी रहती है, उनके लिए भी कमल के फूलों से बनी चाय फायदेमंद हो सकती है। पीरियड्स के दौरान रोजाना 2 कप यह चाय पीने से राहत मिलती है।

कैसे बनाएं कमल के फूलों की चाय : कमल के फूलों से चाय बनाने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी को पैन में डालकर उबाल लें। अब इस उबलते हुए पानी में कमल के फूल डालकर थोड़ी देर तक पकाएं। ऐसा करते समय पानी और कमल के फूल का अनुपात 4:1 रखें। इसे बाद इस चाय को लगभग 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए अलग रख दें। पानी का यह मिश्रण जब ठंडा हो जाए, तो छलनी की मदद से छानकर इसमें थोड़ा सा गुलाब का अर्क डालें। आपकी टेस्टी और हेल्दी कमल के फूल की चाय बनकर तैयार है। आप चाहे तो इस चाय स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर : *यह लेख मात्र सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की राय अवश्य लें।*

"टीबी-मुक्त भारत" बनाने हेतु भारत की प्रतिबद्धता

सबसे बड़ी जानलेवा बीमारियों में से ए, क्षयरोग (टीबी) एक संक्रामक बीमारी है जो दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती है। यह वैश्विक चिंता का एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है। भारत इस बीमारी का सर्वाधिक भार वहन करने वाले देशों में से एक है। केंद्र और राज्य सरकारें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 के तहत वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले ही 2025 तक इसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए, हम इस रोग के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से विचार करें और इस दिशा में भारत की पहल को समझें।

टीबी का वैश्विक-भार

टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (M.tb) के कारण होने वाला एक संक्रामक वायुजनित रोग है। डब्ल्यूएचओ (WHO) का अनुमान है कि लगभग 1.8 बिलियन लोग, जो कि वैश्विक आबादी का लगभग 1/4 हिस्सा है, टीबी से संक्रमित हैं। हर साल लगभग 13 लाख बच्चे टीबी से बीमार पड़ते हैं। यह दुनिया भर में मौतों के लिए उत्तरदायी प्रमुख संक्रामक कारणों में से एक है। पिछले साल, टीबी को कोविड-19 के बाद दुनिया में किसी एक संक्रामक एजेंट से होने वाली मौतों के दूसरे प्रमुख कारण के रूप में दर्ज किया गया। यह एचआईवी/एड्स से लगभग दोगुनी मौतों का कारण रहा। 2022 में, 1.06 करोड़ लोग टीबी से संक्रमित हुए और 14 लाख लोगों की मौत हुई। टीबी के कारण प्रतिदिन 3500 मौतें होती हैं।

क्षयरोग विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य-संबंधी जोखिम कारकों द्वारा गहनता से प्रभावित होता है। ये कारक हैं - कुपोषण, मधुमेह, एचआईवी संक्रमण, मद्य-सेवन से होने वाले विकार और धूम्रपान। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 2020 में वैश्विक स्तर पर, टीबी के अनुमानित 19 लाख मामले कुपोषण के कारण, 7.4 लाख एचआईवी संक्रमण के कारण, 7.4 लाख मद्य-सेवन से उत्पन्न विकारों के कारण, 7.3 लाख धूम्रपान के कारण और 3.7 लाख मधुमेह के कारण थे। हालांकि, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें भिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाली शहरी आबादी में इसका विस्तार अधिक देखा गया है।

विश्व के, 87% टीबी मामलों का भार उच्च संक्रमण वाले 30 देशों पर है। इनमें से, वैश्विक कुल बोझ का दो-तिहाई हिस्सा आठ देशों में पाया गया।

कुल वैश्विक मामलों में भारत की 27% की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसके बाद इंडोनेशिया (10%), चीन (7.1%), फिलीपींस (7.0%), पाकिस्तान (5.7%), नाइजीरिया (4.5%), बांग्लादेश (3.6%) और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (3.0%) का स्थान आता है।

भारत को टीबी-मुक्त बनाने के लिए प्रमुख पहल

यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि यद्यपि क्षयरोग बहुत संक्रामक है, परन्तु यदि इसका यथासमय पता चल जाए और पूरा उपचार हो जाए तो यह पूरी तरह से रोकथाम-योग्य और उपचार-योग्य रोग है।

वैश्विक टीबी की घटनाओं के उच्चतम बोझ से दबी भारत सरकार ने टीबी की समस्या से मिशन मोड में निपटने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने टीबी महामारी को समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है। टीबी एसडीजी लक्ष्य 3.3 का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है: 'एड्स, क्षयरोग, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारियों को समाप्त करना और हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संक्रामक रोगों से 2030 तक निपटना'। परंतु, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में घोषणा की कि भारत वैश्विक लक्ष्य से पांच साल पहले यानी 2025 तक टीबी को देश से ख़त्म कर देगा। इसने नीति-निर्माताओं और टीबी-मुक्त भारत की दिशा में काम करने वाली एजेंसियों को केंद्रित ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। मार्च 2023 में वाराणसी में "स्टॉप टीबी पार्टनरशिप" मीटिंग में, टीबी-मुक्त समाज सुनिश्चित करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, पीएम ने कहा कि "भारत ने 2014 के बाद टीबी से निपटने के लिए जिस प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ खुद को समर्पित किया है, वह अभूतपूर्व है।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह "टीबी के खिलाफ़ वैश्विक-युद्ध का नया मॉडल है"। भारत के प्रयासों को वैश्विक प्रशंसा मिली है। "स्टॉप टीबी पार्टनरशिप" की कार्यकारी निदेशक डॉ. लुसिका दितिउ ने टीबी से निपटने में भारत के प्रयासों एवं "टीबी-मुक्त भारत" पहल की सराहना की। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत 2025 तक टीबी को ख़त्म कर देगा और इससे वैश्विक टीबी के बोझ में भारी कमी आएगी। भारत को 2025 तक टीबी-मुक्त बनने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में दो साल से भी कम समय शेष है, इसलिए आगे बढ़ने का दृष्टिकोण रोग की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना और टीबी के निदान एवं उपचार में सेवाओं के कवरेज को बढ़ाना है। यह देखना उत्साहजनक है कि सरकारों, सहायता एजेंसियों और समुदायों के निरंतर प्रयासों से भारत में टीबी के 'मिसिंग मामलों' (missing cases) की संख्या 2015 में 1 मिलियन से घटकर 2023 में 0.26 मिलियन रह गई है।

2025 तक टीबी से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) को लागू कर रहा है:

टीबी रोगियों का शीघ्र निदान, गुणवत्तापूर्ण दवाओं और उपचार पद्धतियों के साथ शीघ्र उपचार।

निजी क्षेत्र में देखभाल चाहने वाले मरीजों से जुड़ना।

रोकथाम रणनीतियों में उच्च जोखिम/संवेदनशील आबादी में संपर्क का पता लगाना शामिल है।

टीबी उपचार की सफलता दर में वृद्धि

पिछले नौ वर्षों में, एक तिहाई अधिसूचनाएँ निजी क्षेत्र से आने के बावजूद, कार्यक्रम 80% से अधिक की उपचार सफलता दर बनाए रखने में सक्षम रहा है। 2021 में, सफलता दर 84% तक पहुँच गई और 2022 में यह अंशत: बढ़कर 85.5% हो गई। 2023 में, सफलता दर बढ़कर 86.9% हो गई।

नई टीबी-रोधी दवाओं के आने से पड़ा महत्त्वपूर्ण प्रभाव

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अल्पकालीन, सुरक्षित ओरल बेडाक्विलिन युक्त डीआर-टीबी उपचार शुरू किए गए हैं। ये दवाएँ मल्टी-ड्रग-रेसिस्टेंट टीबी रोगियों को फ्लोरोक्विनोलोन के प्रतिरोध के साथ या बिना प्रतिरोध के, कम समय के ऑरल एमडीआर/आरआर (मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट / रिफैम्पिसिन-रेसिस्टेंट) -टीबी उपचार या लंबे समय के ऑरल एम (मल्टीड्रग-रेसिस्टेंट)/एक्सडीआर (व्यापक रूप से दवा-प्रतिरोधी)-टीबी उपचार के हिस्से के रूप में दी जाती हैं। 2022 में, कुल लगभग 31,000 रोगियों को दीर्घकालीन सभी-ऑरल एम/एक्सडीआर-टीबी उपचार और 27,431 रोगियों को अल्पकालीन एमडीआर/आरआर-टीबी उपचार (मौखिक/इंजेक्शन आधारित) पर शुरू किया गया।

2023 में, 63,939 से ज़्यादा मरीज़ों में एमडीआर/आरआर का निदान किया गया और उनमें से 58,527 से ज़्यादा लोगों ने इलाज शुरू किया। इनमें से, लगभग 20,567 मरीज़ों को अल्पकालीन ऑरल एमडीआर/आरआर-टीबी उपचार (9-11 महीने) दिया गया और करीब 29,990 मरीज़ों को दीर्घकालीन एम/एक्सडीआर-टीबी उपचार (18-20 महीने) दिया गया।

निक्षय पोषण योजना के माध्यम से पोषण सहायता

टीबी के लिए कुपोषण एक महत्त्वपूर्ण जोखिम कारक के रूप में पाया जाता है जिसका टीबी रोगियों के स्वास्थ्यलाभ पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सक्रिय टीबी विकसित होने का जोखिम कुपोषित लोगों में स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक होता है। डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट (2017) के अनुसार, सक्रिय टीबी से पीड़ित लोग जो कुपोषण से पीड़ित हैं, आमतौर पर उनमें मृत्यु दर में दो से चार गुना वृद्धि होती है। साथ ही, दवा-प्रेरित (drug-induced) हेपेटोटॉक्सिसिटी का जोखिम भी पाँच गुना है।

इस प्रबल सह-संबंध को देखते हुए, सरकार ने अप्रैल 2018 में 'निक्षय पोषण योजना' (एनपीवाई) की शुरुआत की, जिसके तहत टीबी रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के दौरान पोषण-समर्थन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के रूप में 500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएँगे। अब तक, 1 करोड़ से अधिक टीबी रोगियों को इसका लाभ हुआ है। कुल मिलाकर, मार्च-2024 तक 2859.96 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण किया जा चुका है।

बुनियादी ढाँचे का विस्तार

सक्रिय टीबी मामलों का पता लगाने में नैदानिक आधारभूत ढाँचे (डायग्नोस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) ने अहम भूमिका निभाई है। ठोस प्रयासों के माध्यम से, टीबी प्रयोगशाला सेवाओं के बुनियादी ढाँचे का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में डिजिग्नेटिड माइक्रोस्कोपी केंद्रों (डीएमसी) में 80% की वृद्धि हुई है (2014 में 13583 से 2023 में 24449 तक)। साथ ही, अब तक 6196 नई आणविक नैदानिक प्रयोगशालाएँ (molecular diagnostic laboratories) स्थापित की गई हैं। दवा-प्रतिरोधी टीबी उपचार केंद्रों की संख्या 2014 में 127 से बढ़कर 2022 में 792 हो गई है।

उच्च-स्तरीय फोकस

2023 में जी-20 इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैश्विक-महत्त्व की चुनिंदा चिंताओं की तत्परतापूर्वक वकालत की है और समाधान किया है, जिसमें डिजिटल समाधान का उपयोग करके स्वास्थ्य-सेवाओं की प्रभावशीलता और पहुंच में सुधार करना; औषधीय-विकास और विनिर्माण-क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सहयोग को मज़बूत करना शामिल है। नवंबर 2023 में गुजरात के गांधीनगर में स्वास्थ्य कार्य-समूहों (Health Working Groups) और मंत्रिस्तरीय बैठक में विचार-विमर्श के दौरान "वन हेल्थ" दृष्टिकोण और एंटी-माइक्रोबियल रेज़िस्टेंस (एएमआर) पर विशेष ध्यान दिया गया। इन सभी का भारत और दुनिया की टीबी के खिलाफ़ लड़ाई के साथ गहरा संबंध रहा है।

निष्कर्ष

टीबी से निपटने के लिए समयसीमा और जवाबदेही संरचनाओं के साथ एक व्यापक-आधारित कार्य-योजना की आवश्यकता है, जिसकी समुदायों और विभिन्न हितधारकों और भागीदारों को शामिल करते हुए परिश्रमपूर्वक निगरानी की जाए। डब्ल्यूएचओ ने टीबी के लिए एक बहुक्षेत्रीय जवाबदेही ढांचा (एमएएफ-टीबी) तैयार किया है जिसे 2019 में देशों के साथ साझा किया गया था। इसे राष्ट्रीय कार्य-योजनाओं द्वारा अनुपूरित गया है। अब देशों को इन कार्य-योजनाओं को वैश्विक लक्ष्यों और समयसीमाओं के अनुरूप लागू करना है ताकि दुनिया को टीबी के अभिशाप से मुक्त किया जा सके।

-लेखक : डॉ. मनीषा वर्मा

(भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त महानिदेशक) ये उनके निजी विचार हैं।

10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया

भारत में 7 अगस्त, 2024 को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल, कोलकाता में आयोजित एक बैठक में इसी दिन हुई थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक हिस्से के रूप में इस आंदोलन का उद्देश्य घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को पुनर्जीवित करना था। इस ऐतिहासिक अवसर को याद करने और हमारी हथकरघा परंपरा का जश्न मनाने के लिए, माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य भारत के हथकरघा कामगारों को सम्मानित करना तथा हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। इनमें से 25 लाख से ज्यादा महिलाएं हैं। इस प्रकार, यह क्षेत्र महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वस्त्र मंत्रालय ने देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं।

मैं आपका ध्यान 28 जुलाई 2024 को माननीय प्रधानमंत्री के "मन की बात" की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करने में हथकरघा क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने नए स्टार्टअप उद्यमों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जो हथकरघा उत्पादों और सस्टेनबल फैशन को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से स्थानीय हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें हैशटैग #MyProductMyPride के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करने का भी आग्रह किया।

पिछले कुछ वर्षों में, भारत का हथकरघा क्षेत्र निरंतरता और स्लो फैशन के प्रतीक के रूप में उभरा है। आज, मैं मात्रा की अपेक्षा गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि हम हथकरघा के पुनरुत्थान का जश्न मना रहे हैं अतः इस अवसर पर मैं भारत के लोगों से हथकरघा क्षेत्र में सतत गति बनाए रखने की अपील करता हूं। हथकरघा बुनाई एक विरासत वाली शिल्पकला है जो स्लो, निरंतर और नैतिक फैशन के सिद्धांतों को मूर्त रूप देती है।

पिछले दशक में लगातार सरकारी प्रयासों से फास्ट फैशन से लेकर स्थानीय स्तर पर उत्पादित वस्तुओं में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी गर्व से भारतीय हथकरघा पर बुने हुए कपड़े पहनते हैं और विश्व स्तर पर उनको बढ़ावा भी देते हैं तथा हथकरघा क्षेत्र की सफलता में काफी हद तक उनका योगदान रहा है। अब समय आ गया है कि अधिक से अधिक लोग इस आंदोलन में शामिल हों।

हथकरघा क्षेत्र सस्टेनबिलिटी को बढ़ावा देने के अलावा, महिलाओं और हाशिए पर पहुंच चुके समुदायों को सशक्त बनाने, उनके लिए आर्थिक संभावनाएं प्रदान करने और अपनी शिल्पकला पर उन्हें गर्व करने के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। मैं इस क्षेत्र के उत्थान में कताई, रंगाई और बुनकर के रूप में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता हूं तथा उनके अमूल्य योगदान की सराहना करता हूं। मैं देश भर के पारंपरिक समुदायों और विशेषकर महिलाओं के योगदान को पूरी तरह से मान्यता और सम्मान देता हूं, जिनके बिना हथकरघा क्षेत्र के उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके योगदान को बनाए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए उनके साथ गरिमापूर्ण एवं सम्मानजनक व्यवहार करना जरूरी है। इसके अलावा, हथकरघा क्षेत्र में कई महिला-नेतृत्व वाली सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह भी बने हुए हैं। ये संगठन न केवल प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराते हैं, बल्कि एक सहायता नेटवर्क भी प्रदान करते हैं जो एकजुटता और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ावा देता है। महिला स्वयं सहायता समूह एकजुट होकर, अपने उत्पादों की बेहतर कीमतों के लिए सौदेबाजी कर सकती हैं, बड़े बाजारों तक

पहुंच बना सकती हैं तथा उचित मजदूरी और कार्य करने संबंधी उचित परिस्थितियाँ की भी मांग कर सकती हैं। बुनाई कौशल, डिजाइन नवाचार और एंटरप्रेन्योर क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए शैक्षिक कार्यक्रम और पहलें महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाती हैं। नई तकनीकों में निपुणता प्राप्त करके और आधुनिक डिजाइनों को एक्सप्लोर करके, महिला बुनकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाकर समकालीन बाजारों को आकर्षित कर सकती हैं जो उनके शिल्प की सस्टेनबिलिटी को सुनिश्चित करेगी।

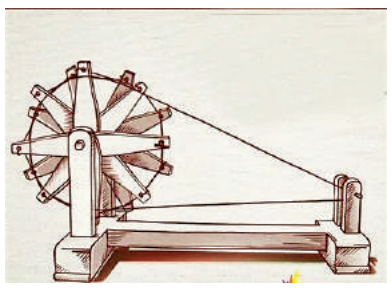

एम्ब्रॉइडरी और प्रिंटिंग द्वारा मूल्य संवर्धन के माध्यम से हथकरघा को बढ़ावा देने से पारंपरिक वस्त्रों में नई जान आती है, तथा अद्वितीय और अत्यधिक वांछनीय उत्पाद तैयार होते हैं। एम्ब्रॉइडरी, सुई के काम से जुड़ी एक जटिल कला है, जो हथकरघा कपड़ों में गहराई और विशेषता पैदा करती है। जरदोजी, कांथा या चिकनकारी जैसी विभिन्न तकनीकों को शामिल करके, कारीगर साधारण हथकरघा वस्त्रों को विस्तृत, अद्वितीय टुकड़ों में बदल देते हैं। इससे न केवल सौंदर्य अपील बढ़ती है बल्कि उत्पादों का बाजार मूल्य भी बढ़ता है, जिससे कारीगरों को बेहतर आर्थिक अवसर मिलते हैं। इन मूल्य संवर्धन तकनीकों को हथकरघा वस्त्रों के साथ संयोजित करने से ऐसे उत्पाद तैयार होते हैं जो पारंपरिक और समकालीन दोनों बाजारों को आकर्षित करते हैं। यह फ्यूज़न न केवल सदियों पुराने शिल्प को संरक्षित और पुनर्जीवित करता है बल्कि हस्तनिर्मित, पर्यावरण-अनुकूल वस्त्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करके सस्टेनबल फैशन को भी बढ़ावा देता है।

हथकरघा उद्योग में प्रौद्योगिकी और नवाचार का एकीकरण बुनकरों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाई को कम करने, उत्पादकता बढ़ाने और इस पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आधुनिक प्रगति ने हथकरघा बुनाई से जुड़े शारीरिक श्रम को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक इफिशएन्ट और अपेक्षाकृत कम श्रम वाली हो गई है। इसके अतिरिक्त, कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन (सीएडी) सॉफ़्टवेयर बुनकरों को बुनाई शुरू करने से पहले उन्हें जटिल पैटर्न और रंग संयोजनों के सुव्यवस्थित प्रयोग हेतु सक्षम बनाता है। इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि त्रुटियों का जोखिम भी कम हो जाता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट प्राप्त होते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स वेबसाइटें बुनकरों को व्यापक बाजारों तक पहुंच प्रदान करती हैं, उन्हें सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ती हैं और बिचौलियों पर निर्भरता को कम करती हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में इस वर्ष, मैं आज सभी से दो प्रतिज्ञाएँ लेने का आग्रह करता हूं; पहला, हम सभी हथकरघा उत्पादों के साथ सेल्फी लेंगे और उसे सोशल मीडिया पर साझा करेंगे; दूसरा, हथकरघा को अपने परिधानों एवं दैनिक जीवन में शामिल करेंगे। प्रत्येक हथकरघा वस्तु अद्वितीय है, जिसे सावधानी एवं बारीकी से बुना जाता है, जो इसके बनाने वाले के समर्पण के साथ-साथ उसके शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। हथकरघा उत्पादों का चयन करके हम न केवल पारंपरिक वस्त्रों की सुंदरता और विविधता को सम्मानित करते हैं, बल्कि कारीगरों की आजीविका में भी योगदान देते हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उनका यह अमूल्य कौशल भावी पीढ़ियों तक पहुंच जाय।

हथकरघा उद्योग में गुणवत्ता, निरंतरता और तकनीक को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। नवीन सामग्रियों एवं प्रक्रियाओं को अपनाकर हथकरघा बुनाई को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। हर किसी को क्षेत्रीय शिल्पकारों और पारंपरिक बुनाई समुदायों का समर्थन करना चाहिए और उनके कपड़ों की खरीदारी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, जिससे इन्हें बनाने वाले लोग और यह क्षेत्र लाभान्वित होता है। हथकरघा वस्तुओं, निष्पक्ष व्यापार, रीजनल मैन्यूफेक्चरिंग, **सस्टेनबिलिटी** और शिल्प कौशल पर ध्यान देने से इस आंदोलन को बढ़ने में मदद मिलेगी और हथकरघा बुनकरों को उनका हक मिलेगा।

हथकरघा उद्योग का समर्थन करके, हम न केवल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं, बल्कि महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के लिए भी प्रयास करते करते हैं और साथ ही, संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) 2030 को भी प्राप्त करते हैं।

-लेखक : गिरिराज सिंह

(केंद्रीय वस्त्र मंत्री)

अमित शाह ने चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई- समन ऐप का लोकार्पण किया गया

• **जालंधर ब्रीज** . चंडीगढ़

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई- समन ऐप का लोकार्पण किया। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया और केन्द्रीय गृह सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि आज यहां उपस्थित सभी लोग 21वीं सदी के सबसे बड़े रिफॉर्म के लागू होने के साक्षी बने हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लाए गए तीन नये कानूनों - भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) - में भारत की मिट्टी की सुगंध और हमारे न्याय के संस्कार हैं। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय देना संविधान का दायित्व है और संविधान की इस स्पिरिट को ज़मीन पर उतारने का माध्यम हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 150 साल पहले बने कानून प्रासंगिक नहीं रह सकते। 1860 और आज के भारत और उस वक्त के शासकों के उद्देश्य और आज हमारे संविधान के उद्देश्यों में बहुत अंतर है लेकिन क्रियान्वयन की मशीनरी वही है। उन्होंने कहा कि वर्षों तक लोगों को न्याय नहीं मिलता था और तारीख पर तारीख मिलती थी। शाह ने कहा कि धीरे-धीरे लोगों का विश्वास सिस्टम पर से उठता जा रहा था। इसीलिए मोदी सरकार ने IPC की जगह BNS, CrPC की जगह BNSS और Evidence Act की जगह BSA लागू करने का काम किया है।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण की बात कही थी जिनमें से एक था गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करना। उन्होंने कहा कि BNS, BNSS और BSA, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भारतीय संसद में और भारत के लोगों के लिए बनाए गए कानून हैंइन तीन नए कानूनों में भारत की मिट्टी की सुगंध और हमारा न्याय का संस्कार है। शाह ने कहा कि इन कानूनों में दंड का कोई प्रावधान नहीं है बल्कि इनका उद्देश्य लोगों को न्याय देना है इसीलिए ये दंड संहिता नहीं बल्कि न्याय संहिता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद पूरी दुनिया में सबसे आधुनिक और तकनीक से युक्त आपराधिक न्याय प्रणाली भारत की होगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए गृह मंत्रालय ने अनेक स्तरों पर प्रशिक्षण और कौशल विकास की व्यवस्था की है। इन कानूनों के बनने से पहले ही फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया गया और आज देश के 8 राज्यों में फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी काम कर रही हैं और वहां से फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्स मिलने भी शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 8 और राज्यों में फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी खोली जाएगी जिससे 36 हज़ार फॉरेन्सिक एक्सपर्ट्स सालाना मिलेंगे।

अमित शाह ने कहा कि नए कानूनों में 7 वर्ष या अधिक सज़ा वाले अपराधों में फॉरेन्सिक टीम की अनिवार्य विज़िट का प्रावधान किया गया है। इससे तकनीकी साक्ष्य आने से दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन क़ानूनों में एक डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन की व्यवस्था की गई है जो प्रॉसीक्यूशन की पूरी प्रक्रिया की लगातार निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि ज़िला और तहसील स्तर तक डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन की पूरी श्रृंखला तैयार की

गई है और इनके अधिकार भी तय किए गए हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन्हें ज़मीन पर उतारने के लिए हमारे पूरे तंत्र की तकनीकी क्षमता बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि ई-साक्ष्य, ई- समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि ई- साक्ष्य के तहत घटनास्थल की सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही ई- साक्ष्य सर्वर पर सेव की जाएगी, जो तुरंत ही कोर्ट में भी उपलब्ध होगी। ई-समन के तहत कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक और जिसे समन भेजा जाना है उस तक भी इसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा। न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेन्सिक, प्रॉसीक्यूशन और प्रिज़न एकसाथ इंटरलिंक्ड हैं, जिससे पुलिस को जांच से संबंधित सभी जानकारी मात्र एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई कर सकेगा। इससे समय और पैसे की बचत होगी और मामले का निपटारा भी जल्दी हो सकेगा।

अमित शाह ने कहा कि इन तीनों नए कानूनों पर सुगम अमल के लिए मोदी सरकार ने कई पहल की हैं। CCTNS से लेकर SHO की ट्रेनिंग और FSL के इंटीग्रेशन तक बहुत काम किया गया है। उन्होंने कहा कि तकनीक को इस पूरी प्रणाली का मुख्य स्तंभ बनाया गया है।सिर्फ चंडीगढ़ में ही 22 IT स्पेशलिस्ट और 125 डाटा एनालिस्ट रखे गए हैं।साथ ही 107 नए कंप्यूटर, सभी थानों में स्पीकर और दो वेब कैमरा लगाए गए हैं, 170 टेबलेट, 25 मोबाइल फोन और 144 नए IT कांस्टेबल भर्ती करने का काम हुआ है। शाह ने कहा कि नए कानूनों के शत प्रतिशत क्रियान्वयन में देश में अगर कोई पहला एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होगा तो वो चंडीगढ़ में होगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के कथन 'स्व' से 'पर' का विचार करने वाले ही असल ज्ञानी हैं और इसे हमारे साइबर सोल्जर्स ने चरितार्थ करने का काम किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नशे की लत के खिलाफ हमारा अभियान मात्र एक सरकारी अभियान नहीं है बल्कि ये हमारी नई पीढ़ी को नशे की लत से बाहर निकालने का अभियान है। उन्होंने कहा कि जो लोग नशे की गिरफ्त में हैं उनकी और उनके परिवारजनों की हीनभावना दूर कर हमें इस बीमारी का इलाज करना चाहिए और इसके प्रति जागरुकता फैलानी चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि तीनों नए कानून और इनके माध्यम से भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों में तकनीक को इस प्रकार से शामिल किया गया है कि आने वाले 50 साल तक ईजाद होने वाली सारी तकनीक को इसमें समाहित कर लिया गया है। शाह ने कहा कि हमारे संविधान की स्पिरिट के अनुसार citizen-centric कानून बनाए गए हैं और इनका पूर्ण क्रियान्वयन होने के बाद किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में फैसला आ जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों के बारे में जनजागृति लाने की जितनी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय, राज्य सरकारों या न्यायाधीशों की है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की भी है। गृह मंत्री ने चंडीगढ़वासियों से अनुरोध किया कि वे इन कानूनों के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन से अधिकृत रूप से स्पष्टता मांगें।गृह मंत्री ने सभी से अफवाहों से दूर रहने और इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए सक्रिय और रचनात्मक योगदान देने की अपील की।

महिला सहित दो नशा तस्कर फिरोज़पुर से काबू, 6.6 किलो हेरोइन व 6 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों अनुसार पंजाब पुलिस पंजाब को नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/फिरोजपुर

नशे के विरुद्ध शुरु किए जंग दौरान सरहद पारों नशे की तस्करी में शामिल नेटवर्क के ख़िलाफ़ बड़ी सफलता हासिल करते फ़िरोज़पुर पुलिस ने 6.65 किलो हेरोइन और 6 लाख रुपए की ड्रग मनी सहित दो नशा तस्करों, जिनमें से एक महिला है, को गिरफ़्तार किया है। यह जानकारी देते डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहाँ बताया कि पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान सिमरन कौर उर्फ इंदु (38) निवासी मोगा और गुरजोत सिंह (28) निवासी जैमल वाला मोगा के तौर पर हुई है। गिरफ़्तार किये गए दोनों आरोपियों का अपराधिक रिकार्ड है और आरोपी सिमरन ख़िलाफ़ ऐनडीपीऐस एक्ट, जेल एक्ट आदि से संबंधित कम से- कम 15 अपराधिक मामले दर्ज है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि फ़िरोज़पुर पुलिस को भरोसेयोग्य सूचना मिली थी कि आरोपी सिमरन और गुरजोत सरहद पार ड्रोन के द्वारा फेंकी गई नशे की बड़ी खेप हासिल करने के बाद इसको अपनी टोइटा इनोवा कार रजिस्ट्रेशन नंबर डीएल 12सीसी6003 में किसी को डलिवर करने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि तेज़ी के साथ कार्यवाही करते हुए सी. आई. ए. फिरोजपुर की पुलिस टीमों ने पुरानी मुद्दकी रोड पर नाका लगा कर दोनों मुलजिमों को गिफतार कर लिया और उनके कब्ज़े से इनोवा कार में छिपा कर रखी 6. 65 किलो हेरोइन सहित 6 लाख रुपए की ड्रग मनी बरामद करने के साथ- के साथ उनका वाहन भी ज़ब्त कर लिया।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अगले- पिछले संबंधों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। सीनियर पुलिस कप्तान (एसएसपी) फ़िरोज़पुर सोमया मिश्रा ने बताया कि तकनीकी जानकारी के आधार पर सीआईए पुलिस टीम ने सफलतापूर्वक कार्यवाही को अंजाम दिया और बुद्धवार देर रात को आरोपियों को नशे की खेप और ड्रग मनी सहित काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान आधारित नशा तस्कर और जिन व्यक्तियों को यह खेप पहुंचायी जानी थी, की पहचान के लिए आगे वाली जांच जारी है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा एफ के अंतर्गत गिरफ़्तार किए गए तस्करों की ग़ैर- कानूनी जायदाद को ज़ब्त करने के लिए भी कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी।

1.6 किलोग्राम अफीम के साथ एक गिरफ्तार

सीपी ने शहर से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

• **जालंधर ब्रीज जालंधर**

पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में जालंधर पुलिस कमिश्नरेट ने शहर में अफीम सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक गिरोह शहर में अफीम की तस्करी कर रहा है। उन्होंने कहा कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने राज्य में सतर्कता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन डिवीजन 1 जालंधर की एक टीम सीजेएस पब्लिक स्कूल सर्विस लेन जीटी रोड जालंधर के पास मौजूद थी, जब उन्होंने बिधिपुर गांव की तरफ से एक व्यक्ति को हैंडबैग के साथ आते देखा। स्वपन शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने उक्त व्यक्ति को रोका और उसके हैंडबैग की गहनता से तलाशी ली, जिसमें से 1.6 किलोग्राम अफीम बरामद हुई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना डिवीजन नंबर 1 में एफआईआर 111 दिनांक 03-08-2024 के तहत 18-61-85 एनडीपीएस एक्ट दर्ज किया है। स्वपन शर्मा ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह एक रिक्शा चलाता था पर आर्थिक तंगी के कारण उसने रोजी-रोटी कमाने के लिए अफीम बेचनी शुरू कर दी।

पुलिस आयुक्त ने कहा कि जांच जारी है और अधिक विवरण, यदि कोई है, बाद में साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी का अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। स्वपन शर्मा ने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है और शहर से इस समस्या को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है।

पंजाब पुलिस ने बैंकों व वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा का लिया जायजा

500 से अधिक पुलिस पार्टियों ने राज्यभर में 3826 बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में की चेकिंग: विशेष डीजीपी अर्पित शुक्ला

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के मद्देनजर चल रही मुहिम के हिस्से के रूप में पंजाब पुलिस ने गुरुवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी वित्तीय संस्थाओं- जिनमें बैंकों, नॉन-बैंक वित्तीय कंपनियों, गोल्ड लोन और मनी एक्सचेंजर्स शामिल हैं, की सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए विशेष ऑपरेशन चलाया। यह ऑपरेशन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के निर्देशों पर चलाया गया।

विशेष डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अर्पित शुक्ला ने बताया कि सीपी/एसएसपी को इस ऑपरेशन की व्यक्तिगत निगरानी करने और ऑपरेशन को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए गजटेड रैंक के अधिकारियों की निगरानी में आवश्यक पुलिस टीमों की तैनाती के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस पार्टियों को सुरक्षा गार्डों की तैनाती को सुनिश्चित करने के साथ-साथ संवेदनशील संस्थानों में अलार्म और सीसीटीवी कैमरे लगाने/कार्यशील बनाने के निर्देश भी दिए गए थे। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन राज्य के सभी 28 पुलिस जिलों में चलाया गया, जिसमें 2500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती वाली 500 से अधिक पुलिस पार्टियों ने एस.पी./डी.एस.पी. की निगरानी में 3826 वित्तीय संस्थानों की चेकिंग की, जिनमें 2516 बैंक, 389 एन.बी.एफ.सी., 360 गोल्ड लोन और 561 मनी एक्सचेंजर्स शामिल हैं।

विशेष डीजीपी ने बताया कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय संस्थानों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जो सामान्यतः समाज विरोधी तत्वों के निशाने पर होते हैं, और आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करना था।

इस दौरान पुलिस टीमों ने ऑपरेशन के दौरान बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के आसपास घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों की भी जांच की।

चैकिंग दौरान 12 स्कूल वाहनों के चालान

जालंधर ब्रीज. भोगपुर

क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी (आरटीओ) जालंधर अमनप्रीत सिंह की हिदायतों पर आज यहाँ सेफ स्कूल वाहन पालिसी के अंतर्गत स्कूल वाहनों की चैकिंग की गई, जिस दौरान यहाँ के एक प्राईवेट स्कूल के एक दर्जन स्कूली वाहनों के चालान किए गए। आरटीओ अमनप्रीत सिंह ने जानकारी देते बताया कि चैकिंग दौरान 12 स्कूल वाहन ऐसे थे, जो सेफ स्कूल वाहन पालिसी की शर्तों पूरी नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ स्कूल बसों के चालकों ने वर्दी नहीं पहनी थी, कुछ वाहनों में अटेंडेंट नहीं थे और कुछ वाहन अनफिट्ट थे। जबकि कुछ स्कूल वाहनों के ज़रुरी दस्तावेज़ पूरे न होने के कारण चालान किए गए है।

उन्होंन बताया कि उक्त प्राईवेट स्कूल के वाहनों बारे उनको दफ़्तर की ई- मेल के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर तुरंत कार्यवाही करते एआरटीओ विशाल गोयल की ड्यूटी लगाई गई, जिन्होंने स्कूल के बाहर लिंक रोड पर नाका लगा कर स्कूली वाहनों की चैकिंग की।

आरटीओ ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी किस्म का समझौता बरदाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी स्कूली वाहनों की चैकिंग जारी रहेगी। उन्होंने स्कूल प्रबंधकों को हिदायत करते कहा कि यह यकीनी बनाया जाए कि स्कूल वाहन रोड सेफ्टी नियमों और सेफ स्कूल वाहन पालिसी की शर्तें पुरी करते हों। इसके साथ ही उनके माता-पिता को भी अपील की कि यदि उनके बच्चो की स्कूल वेन/ बस में किसी प्रकार की कमी नज़र आती है तो स्कूल मैनेजमेंट के ध्यान में लाए ताकि सेफ स्कूल वाहन पालिसी को सौ प्रतिशत लागू किया जा सके।

पंजाब पुलिस ने विभिन्न स्कूलों में यौन व बाल शोषण पर सेमिनार आयोजित किए

सेमिनार में सी.पी.आर.सी सेवाओं, साइबर अपराध, ट्रैफिक नियमों के बारे में और नए कानूनों पर भी चर्चा हुई

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

स्पेशल डीजीपी कम्युनिटी अफेयर्स डिवीजन पंजाब के आदेशों का पालन करते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने विभिन्न स्कूलों में सेमिनार आयोजित किए। इन सेमिनारों की देखरेख सुखविंदर सिंह पीपीएस, एडीसीपी मुख्यालय और जिला सामुदायिक पुलिस अधिकारी द्वारा की गई और इन सेमिनारों में सांझ केंद्रों के कर्मचारियों ने भी भाग लिया। हाल के दिनों में कमिश्नरेट पुलिस ने एस.के.एस पैराडाइज स्कूल दकोहा, डी.एम.एस स्कूल मॉडल टाउन, एम.जी.एन खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर कैंट और दोआबा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोआबा चौक जालंधर में सेमिनार आयोगित किये गये।

सेमिनार का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गुड टच-बैड टच, यौन उत्पीड़न और बाल शोषण जैसे विषयों पर शिक्षित करना था। इसके अलावा सेमिनार में सांझ द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं, ऑनलाइन साइबर क्राइम और ट्रैफिक नियमों के बारे में भी बताया गया। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को नए लागू कानूनों, 112, 1930 जैसे आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों और नाबालिगों और उनके माता-पिता दोनों के लिए कम उम्र में ड्राइविंग के परिणामों के बारे में सूचित किया गया।

इंडियन आयल जालंधर डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारम्भ

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसो. की तरफ से रायजादा हंसराज स्टेडियम में इंडियन ऑयल जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 11 अगस्त तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का शुभारम्भ वीरवार को डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने किया। इसके साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक एयर कंडीशंड जिम्नेजियम एवं सिंथेटिक कोर्ट भी खिलाडिय़ों को समर्पित किया। इस मौके पर डीबीए के सचिव एवं पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी रितिन खन्ना ने बताया कि आज शुरू हुई चैंपियनशिप में 35 प्रतिस्पर्धाओं में 600 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगले चार दिनों में 500 मुकाबले खेलें जायेंगे। चैंपियनशिप के दौरान फ्री रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था के साथ-साथ मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है। डीबीए के 50 साल के इतिहास में पहली बार विजेताओं को 5 लाख के आकर्षक व नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आज उद्घाटन समारोह के दौरान अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मान्या रल्हण, अभिनव ठाकुर और राम लखन को डीबीए की तरफ से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

लोगों को उनके दरवाजे पर मिल रही सरकारी सेवाएं : महिंद्र भक्त

• **जालंधर ब्रीज.** जालंधर

पंजाब सरकार के प्रयास 'आप दी सरकार, आप दे द्वार' के अंतर्गत आज यहाँ भारगो कैंप में विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें विधान सभा हलका जालंधर पश्चिमी से विधायक महिंद्र भक्त और डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने पहुंच कर लोगों की मुश्किलें सुनी और उचित हल के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा- निर्देश दिए।

इस मौके विधायक ने कहा कि पंजाब सरकार की इस पहल से लोगों को उनके दरवाजे पर सरकारी सेवाएं मिल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य भर में कैंप लगा कर लोगों को अपने घरों के नज़दीक ही अपने प्रशासकीय काम करवाने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह कैंप लोगों के लिए बेहद लाभदायक साबित हो रहे है क्योंकि इन कैंपों में न केवल एक ही छत नीचे अलग- अलग सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही है बल्कि अलग- अलग विभागों के अधिकारी लोगों के मामलों की सुनवाई करके उपयुक्त हल भी यकीनी बना रहे है।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि आज के इस कैंप में सामाजिक सुरक्षा, स्त्री और बाल विकास, पावरकाम,लेबर, सेहत, जल स्पलाई और सैनीटेशन, पंजाब मंडी बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, मार्किट समिति जालंधर, जालंधर नगर निगम और सेवा केंद्र सहित अलग-अलग विभागों द्वारा अपने-अपने स्टाल लगा कर लोगों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के साथ उनकी मुश्किलों की सुनवाई की गई।

कलेक्टर रेट बढ़ाने से रियल एस्टेट कारोबार पर पड़ेगा प्रतिकूल असर : प्रताप बाजवा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने गुरुवार को पंजाब में भूमि की कलेक्टर दर बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की। एक खबर का हवाला देते हुए बाजवा ने कहा कि पटियाला जिले में कलेक्टर दरों में अब तक काफी वृद्धि की गई है। इस दर में 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में कलेक्टर रेट जल्द बढ़ाए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। यह न केवल पंजाब के रियल एस्टेट व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, बल्कि आम लोगों को भी झटका देगा जो घर बनाने या छोटे व्यवसाय खोलने के लिए जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं। बाजवा ने कहा कि सरकार वास्तव में आम लोगों की जेब काटने की योजना बना रही है, जो पहले से ही महंगाई के प्रभाव से जूझ रहे हैं।

समाचार रिपोर्ट में राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि वे 6,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को छूने के लिए इसके तहत राजस्व में 1,800 करोड़ रुपये की वृद्धि करने की योजना बना रहे हैं।

बाजवा ने कहा कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार खत्म करके 34,000 करोड़ रुपये और खनन से 20,000 करोड़ रुपये सहित अन्य माध्यमों से राजस्व एकत्र करने का वादा किया था। क्या मुख्यमंत्री भगवंत मान बता सकते हैं कि इन वादों का क्या हुआ? विपक्ष के नेता ने कहा कि यह भी संभव है कि आप सरकार के इस कदम से कालाबाजारी बढ़े। इसके अलावा आप सरकार की गलत नीतियों के चलते पंजाब के उद्योगपति पहले ही दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं और अब जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ने से रियल एस्टेट कारोबार को बड़ा झटका लगने वाला है।

कर अधिकारियों को 16 अगस्त तक शेष फर्मों की ओर से बकाया का निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन शेष फर्मों तक निजी तौर पर पहुंचें, जिन्होंने अभी तक पंजाब यकमुश्त निपटारा (संशोधन) योजना (ओ.टी.एस.-3) का लाभ नहीं लिया है, और उन्हें इस योजना की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2024 तक आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। इस पहल का उद्देश्य ओ.टी.एस-3 का लाभ उठाने से वंचित रह गई फर्मों को इस योजना के अंतर्गत अपने कर बकाया का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

पंजाब भवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ओ.टी.एस.-3 के तहत हुई प्रगति का मूल्यांकन किया और 30 जून की समय सीमा से चूक गए शेष 11,130 डीलरों जिन्होंने अभी इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना है, तक पहुंचने के लिए डिवीजन और जिला स्तर के अधिकारियों को अपने प्रयास तेज करने के लिए कहा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर विकास प्रताप, आबकारी एवं कर कमिश्नर वरुण रूजम, कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा डिवीजन और जिला स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ओटीएस-3 की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जहां कर राजस्व में 141.58 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, वहीं 59,182 डीलरों ने इस योजना का लाभ लिया।

सरकारी बाल घरों में रह रहे बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 'मान सरकार' की ऐतिहासिक पहल

कैबिनेट मंत्री द्वारा कला आधारित उद्देश्य के माध्यम से बच्चों को सक्षम बनाने के लिए नालंदावे फाउंडेशन के साथ समझौता करने की घोषणा

• **जालंधर ब्रीज.** चंडीगढ़/एसएएस नगर

सरकारी बाल घरों और ऑब्जर्वेशन होम्स/विशेष घरों में रहने वाले बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ऐतिहासिक पहल करते हुए, सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास संबंधी कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज छतबीड़ में चेन्नई आधारित एनजीओ नालंदावे फाउंडेशन के साथ समझौता (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की ताकि इन बच्चों के बेहतर पुनर्वास के लिए कला-आधारित तंदुरुस्ती और परिवर्तन परियोजना शुरू की जा सके। इस कदम को पंजाब राज्य में अपनी तरह का पहला और अभिनव कदम बताते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि हर बच्चे का कोई न कोई सपना होता है, लेकिन सरकारी बाल देखभाल संस्थाओं (सी.सी.आई.) में परिवारों के बिना रह रहे बच्चों के मामले में स्थिति कुछ दयनीय हो जाती है। बाल घरों में बच्चे बहुत कोमल स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनके भविष्य को दिशा देने के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। इन मामलों में यह एनजीओ, जो पहले ही तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड और दिल्ली सी.सी.आई. में काम कर चुका है, इन बच्चों की बेहतरी के लिए पढ़ाई-लिखाई जैसे बुनियादी साक्षरता कौशल में आवश्यक सहायता प्रदान करने और 6-18 साल की उम्र के बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग में मददगार साबित होगा। इस कार्यक्रम को पहले चरण में 6 सरकारी बाल घरों और 5 निगरानी/विशेष घरों में चलाया जाएगा और अगले चरण में इसका दायरा सरकारी सहायता प्राप्त 4 बाल घरों तक बढ़ाया जाएगा।

घरेलू क्रिकेट से मिलते हैं खिलाड़ी : रोहित शर्मा

कहा- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है हमारा घरेलू क्रिकेट

फोटो-बीसीसीआई

स्पोर्ट्स डेस्क : टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि टेस्ट और वनडे के लिए टीम के चयन के लिए रणजी ट्रॉफी जैसे घरेलू टूर्नामेंट काफी अहमियत रखते हैं। उन्होंने माना कि चयन के लिए आईपीएल भी एक अहम टूर्नामेंट है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके आने से भारत की प्रमुख घरेलू प्रतियोगिताओं का महत्व कम नहीं हुआ है। बता दें श्रीलंका के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज में भारत को 2-0 से हार का सामना करना पड़ा और सीरीज का पहला मैच टाई रहा था। भारत 1997 के बाद श्रीलंका से वनडे सीरीज हारा है। इस मैच में श्रीलंका की धीमी पिचों पर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए। मैच के बाद रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि क्या वह भारत के युवा बल्लेबाजों को घरेलू क्रिकेट में अधिक खेलने की सलाह देंगे? इसके जवाब में हिटमैन ने स्पष्ट किया कि टेस्ट और वनडे टीमों के लिए खिलाड़ियों को चुनने के मामले में भारत का घरेलू ढांचा सबसे महत्वपूर्ण है। रोहित शर्मा ने कहा कि हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है- यह सुनिश्चित करना कि जो खिलाड़ी उपलब्ध हैं, वे रणजी ट्रॉफी खेलें। हमारा घरेलू क्रिकेट हमारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी है।

कप्तान ने आगे कहा कि हमें घरेलू सर्किट से खिलाड़ी मिलते हैं, आईपीएल से नहीं। जब आप टेस्ट और वनडे क्रिकेट के लिए खिलाड़ियों का चयन करते हैं तो इस बात पर काफी चर्चा होती है कि रणजी ट्रॉफी, वनडे फॉर्मेट, सैयद मुश्ताक अली और इस तरह की अन्य प्रतियोगिताओं में कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। रोहित ने कहा कि आईपीएल निश्चित रूप से एक ऐसा फॉर्मेट है जहां चुनौतियां अलग हैं। यह दोनों की प्रतिस्पर्धा है। आईपीएल भी हमारा क्रिकेट है। यह इंडियन प्रीमियर लीग है। अंत में जो भी इन सभी टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे ही चुना जाएगा।

Printed, Published & Owner by ATUL SHARMA & Printed at SARANGLE PRINTERS, BASTI GUZAN JALANDHAR (PUNJAB) and Published from ATUL SHARMA, NN453 GOPAL NAGAR JALANDHAR (PUNJAB)
Editor : ATUL SHARMA*
*Responsible for selection of News under the PRB ACT. PUNHIN/2019/77863, All Rights Reserved. Reproduction in whole or in Part without permission is prohibited. All disputes shall be settled at Jalandhar jurisdiction only.